भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2649

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन 1946 (शक) को दिया जाना है

एफएटीएफ में भारत की रेटिंग

2649. डॉ. के. सुधाकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतिम एफएटीएएफ समीक्षा में देश की रेटिंग का ब्यौरा क्या है और इसमें समान स्थान पर रहने वाले देशों की संख्या कितनी है;
(ख) देश एफएटीएएफ के साथ किस प्रकार लगातार जुड़ा रहा है;
(ग) क्या वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू) ने एसटीआर की प्रसार क्षमताओं में सुधार किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार के पास देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को कोई ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या बैंकों अथवा बीमा कंपनियों के निजीकरण अथवा हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(छ) सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों और गैर-कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) 40 सिफारिशों में से, भारत को 37 सिफारिशों में अनुपालन या काफी हद तक अनुपालन रेटिंग प्राप्त हुई। इसे 3 सिफारिशों में आंशिक रूप से अनुपालन रेटिंग मिली। किसी भी सिफारिश को गैर-अनुपालन के रूप में रेट नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, भारत को 'नियमित अनुवर्ती' में रखा गया, जो एफएटीएएफ पद्धति के तहत मूल्यांकन किए जा रहे किसी भी देश द्वारा सर्वोत्तम संभव रेटिंग है। एफएटीएएफ में केवल तीन अन्य जी20 देश हैं जिन्हें यह रेटिंग मिली है। यह अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। इस पर एक विस्तृत नोट अनुलग्नक-I में है।

(ख) भारत आपसी मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान एफएटीएफ के साथ लगातार जुड़ा रहा। दो साल की अवधि में, राजस्व विभाग ने आपसी मूल्यांकन के दौरान एफएटीएफ के साथ भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया। यह सफलता विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), राज्य प्राधिकरणों, न्यायपालिका, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, स्व-नियामक संगठनों, वित्तीय संस्थानों और अन्य व्यवसायों के प्रतिनिधियों वाली एक विविध, बहु-विषयक टीम के असाधारण प्रयासों और अमूल्य योगदान से प्रेरित थी।

पारस्परिक मूल्यांकन के बाद भी, भारत मजबूत और जोखिम-आधारित एएमएल/सीएफटी नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार एफएटीएफ के साथ जुड़ता रहता है। भारत संचालन समूह का सदस्य है। अन्य तरीके जिनसे भारत लगातार एफएटीएफ के साथ जुड़ता है, उनका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) फिननेट 2.0, उन्नत आईटी प्रणाली के कार्यात्मक होने के साथ, रिपोर्टिंग संस्थाओं (आरईएस) से प्राप्त एसटीआर के आधार पर मामलों के प्रसार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फिननेट 2.0 उन्नत विश्लेषण का उपयोग करता है और एफआईयू-भारत की सभी सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के लिए शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करता है। फिननेट 2.0 लाइव हो गया है और इसका प्रभाव पिछले 3 वर्षों में प्रसारित एसटीआर के आंकड़ों से स्पष्ट है : -

2022-23	2023-24	2024-25 (फरवरी 2025 तक)
80,546	1,14,199	4,36,287

एफआईयू-भारत परिचालन विश्लेषण (ओए) और प्राथमिकता एसटीआर के रूप में भी एसटीआर प्रसारित करता है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	साझा किए गए ओए की संख्या	साझा की गई प्राथमिकता वाली एस.टी.आर.एस. की संख्या
2021-22	62	1613
2022-23	202	2682
2023-24	139	2750

कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा साझा की गई प्राथमिकता एसटीआर में से 40% उपयोगी पाई गई हैं। एफआईयू-भारत द्वारा साझा की गई आसूचना के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित हासिल किया गया है:-

1. 983.40 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई तथा 2763.30 करोड़ रुपये की आपराधिक आय की पहचान की गई।
2. 10,998 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।
3. 461 किलोग्राम मादक पदार्थ/मनोप्रभावी पदार्थ जब्त किए गए।
4. रिपोर्टिंग संस्थाओं पर एफआईयू द्वारा विनियामक कार्रवाई: 39.14 करोड़ रुपए का जुर्माने सहित 211 अनुपालन आदेश जारी किए गए।
5. एमएल/टीएफ और अन्य अपराधों में 184 गिरफ्तारियां की गईं।

(ङ) भारत को वित्त वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 62,483 मिलियन अमरीकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2000-01 से वित्त वर्ष 2024-25 तक इस एफडीआई प्रवाह के विवरण के लिए कृपया अनुलग्नक-III देखें।

(च) वर्तमान में, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("आईडीबीआई बैंक") रणनीतिक विनिवेश से गुजर रहा है, जिसमें भारत सरकार (जीओआई) और एलआईसी क्रमशः 30.48% और 30.24% इक्विटी का विनिवेश कर रहे हैं, जो आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का कुल 60.72% है, साथ ही बैंक में प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी कर रहे हैं।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों में, जो सूचीबद्ध हैं, अल्पमत हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से विनिवेश, समय-समय पर प्रचलित बाजार स्थितियों और निवेशक हित के आधार पर विभिन्न सेबी-अनुमोदित तरीकों के माध्यम से किया जाता है, इस शर्त के अधीन कि भारत सरकार विनिवेश के बाद 52% शेयरधारिता बरकरार रखे।

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 14 मार्च, 2022 को माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य निम्न आय वाले परिवारों की अत्यधिक ऋणग्रस्तता की चिंताओं को दूर करना, माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने के लिए प्रतिस्पर्धी ताकतों को सक्षम बनाना, ग्राहक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन शुरू करना है। इन अनुदेशों में अन्य बातों के अलावा, आरबीआई की सभी आरई के लिए माइक्रोफाइनेंस ऋणों की एक समान परिभाषा, परिवार की आय के प्रतिशत के रूप में ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान के कारण बहिर्वाह पर सीमा, कोई पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं और माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए ऋणाधार की कोई आवश्यकता नहीं आदि शामिल हैं।

आरबीआई एनबीएफसी क्षेत्र को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए श्रेणीबद्ध नियामक और पर्यवेक्षी संरचना का पालन करता है। बेस लेयर एनबीएफसी वे हैं जिनमें कम परिसंपत्ति आकार और अंतर्संबंध के मद्देनजर कम जोखिम माना जाता है। उन्हें सबसे कम जोखिम वाला माना जाता है और इसलिए वे हल्के-फुल्के नियमों के अधीन हैं। मध्य लेयर में एनबीएफसी को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए वे उन्नत विवेकपूर्ण नियमों और विस्तृत विवेकपूर्ण, आचरण और शासन नियमों जैसे पूंजी पर्याप्तता, जोखिम सीमा, कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंड आदि के अधीन हैं। ऊपरी लेयर में एनबीएफसी पूंजी, बड़े एक्सपोजर ढांचे, शासन, प्रकटीकरण और पारदर्शिता, लिस्टिंग आदि के मामले में कड़े बैंक जैसे नियमों के अधीन हैं। पर्यवेक्षी प्रयास भी आनुपातिक रूप से ऊपरी लेयर और मध्य लेयर में बड़े एनबीएफसी पर केंद्रित हैं।

एनबीएफसी के लिए विनियामक निर्देशों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात विवेकपूर्ण विनियमन और व्यावसायिक आचरण विनियमन। एक व्यापक-विवेकपूर्ण विनियामक के रूप में, आरबीआई एनबीएफसी के लिए कुछ विवेकपूर्ण विनियमन निर्धारित करता है, जो अनुलग्नक-IV में सूचीबद्ध हैं।

अनुलग्नक - I

एफएटीएफ में भारत की रेटिंग

2024 में एफएटीएएफ द्वारा भारत का पारस्परिक मूल्यांकन किया गया, जिसमें एफएटीएएफ की 40 अनुशंसाओं के साथ देश के अनुपालन और 11 इम्मिडिएट आउटकम (आईओ) में इसके धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन किया गया। भारत ने **नियमित अनुवर्ती कार्रवाई** के तहत रखे जाने से सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त किया, जो एक मजबूत और सुदृढ़ एएमएल/सीएफटी ढांचे का संकेत देता है।

1. इम्मिडिएट आउटकम में भारत की रेटिंग (आईओ)

भारत के एएमएल/सीएफटी ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन 11 इम्मिडिएट आउटकम के आधार पर किया गया, जिन्हें **उच्च/पर्याप्त प्रभावशीलता (एचई/एसई), मध्यम प्रभावशीलता (एमई) या कम प्रभावशीलता (एलई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रभावशीलता के 11 उपायों में से 6** में भारत को पर्याप्त रूप से प्रभावी और **5** में मध्यम रूप से प्रभावी माना गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की न्यून प्रभावशीलता रेटिंग **शून्य** है। भारत की रेटिंग इस प्रकार है:

इम्मिडिएट आउटकम	रेटिंग
आईओ.1 - जोखिम, नीति और समन्वय	एसई
आईओ.2 - अंतरराष्ट्रीय सहयोग	एसई
आईओ.3 - पर्यवेक्षण	एमई
आईओ.4 - निवारक उपाय	एमई
आईओ.5 - कानूनी व्यक्ति और व्यवस्थाएं	एसई
आईओ.6 - वित्तीय आसूचना	एसई
आईओ.7 - एमएल जांच और अभियोजन	एमई
आईओ.8 - जब्ती	एसई
आईओ.9 – टीएफ जांच और अभियोजन	एमई
आईओ.10 - टीएफ निवारक उपाय और वित्तीय स्वीकृति	एमई
आईओ.11 - पीएफ वित्तीय स्वीकृति	एसई

2. 40 एफएटीएएफ अनुशंसाओं में भारत की रेटिंग

एफएटीएएफ 40 अनुशंसाओं के साथ तकनीकी अनुपालन का मूल्यांकन करता है, जिन्हें **अनुपालन (सी), बड़े पैमाने पर अनुपालन (एलसी), आंशिक रूप से अनुपालन (पीसी) या गैर-अनुपालन (एनसी) के रूप में रेट किया जाता है। भारत ने 40 में से 37 अनुशंसाओं** पर अनुपालन/बड़े पैमाने पर अनुपालन रेटिंग हासिल की । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत की गैर-अनुपालन रेटिंग **शून्य है** । भारत की रेटिंग नीचे संक्षेप में दी गई है:

रेटिंग	संख्या
अनुपालक/बड़े पैमाने पर अनुपालक (सी/एलसी)	37
आंशिक रूप से अनुपालक (पीसी)	3
गैर-अनुपालन (एनसी)	0

3. एफएटीएफ अनुवर्ती श्रेणियां और भारत की स्थिति

एफएटीएएफ मूल्यांकित क्षेत्राधिकारों को उनके अनुपालन के आधार पर विभिन्न अनुवर्ती श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। ये हैं:

- **नियमित अनुवर्ती कार्रवाई** : ऐसे देश जो बिना किसी बड़ी कमी के मजबूत एएमएल/सीएफटी ढांचा प्रदर्शित करते हैं। यह पारस्परिक मूल्यांकन के एफएटीएएफ द्वारा दी जाने वाली रेटिंग की **उच्चतम श्रेणी है**। वे समय-समय पर अदयतित जानकारी के माध्यम से सुधारों से संबंधित एफएटीएएफ को रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध कराएगें। नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अपेक्षाएँ निम्नानुसार हैं:

नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अपेक्षाएँ	**भारत का एमईआर परिणाम**
40 अनुशंसाओं में से 32 से अधिक सी/एलसी	भारत के 40 में से **37 सी/एलसी सिफारिशें** प्राप्त हुईं
'बिग 5 रिक में से 3 या अधिक सी/एलसी	भारत के सभी 'बिग 5 रिकॉर्ड्स' में **सी/एलसी है**
IOs में 5 या अधिक 'पर्याप्त /उच्च प्रभावशीलता' रेटिंग	भारत के **6** 'पर्याप्त /उच्च प्रभावशीलता' रेटिंग प्राप्त हुई हैं
'प्रभावशीलता के निम्न स्तर' की कोई अपेक्षाएँ नहीं है	भारत के किसी भी आईओ में **'प्रभावशीलता का निम्न स्तर'** नहीं मिला है

- **उन्नत अनुवर्ती कार्रवाई** : मध्यम कमियों के कारण जिन देशों को अधिक गहन निगरानी की आवश्यकता है। उन्हें बार-बार, आम तौर पर वार्षिक आधार पर, रिपोर्ट करने और कमियों को दूर करने में प्रगति प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।
- **ग्रे लिस्ट** : रणनीतिक कमियों वाले देश जिनमें महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। इन देशों की जांच अधिक की जाती है और उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के जोखिम से बचने के लिए अपने एएमएल/सीएफटी उपायों को मजबूत करने के लिए एक कार्य योजना लागू करने की आवश्यकता होती है।
- **ब्लैकलिस्ट** : गंभीर कमियों वाले देश जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये क्षेत्राधिकार एफएटीएएफ की चिंताओं को दूर करने में विफल रहे हैं और वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की ओर से उचित परिश्रम बढ़ाने सहित जवाबी उपायों के अधीन हैं।

भारत को **नियमित अनुवर्ती श्रेणी** में रखा गया है, जो दर्शाता है कि इसका एएमएल/सीएफटी ढांचा मजबूत है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। नियमित अनुवर्ती कार्रवाई पारस्परिक मूल्यांकन का सबसे अच्छा संभावित परिणाम है।

4. वैश्विक तुलना

एफएटीएएफ की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 38 सदस्य देशों में से **12** देश नियमित अनुवर्ती श्रेणी में हैं, जिसमें भारत भी शामिल है (रूस को नियमित अनुवर्ती रेटिंग मिली थी, लेकिन इसकी एफएटीएएफ सदस्यता निलंबित कर दी गई है)। भारत के अलावा, **ब्रिटेन, फ्रांस और इटली** ही ऐसे जी-20 देश हैं जिन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। यहाँ तक कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान आदि जैसे प्रमुख जी7 देशों को भी उन्नत अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया है। यह मजबूत एएमएल/सीएफटी व्यवस्था के साथ अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

अनुलग्नक - II

देश किस तरह एफएटीएएफ के साथ लगातार जुड़ा हुआ है

भारत एफएटीएएफ के साथ निरंतर और सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। भारत एफएटीएएफ की सभी कार्य दल बैठकों में भाग लेता है, नीति निर्माण और तकनीकी चर्चाओं में योगदान देता है। यह **एशिया/प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग समूह** (एपीजी) और **यूरेशियन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने वाले समूह** (ईएजी) का सक्रिय सदस्य है, ये दोनों ही एफएटीएएफ-शैली के क्षेत्रीय निकाय (एफएसआरबी) हैं।

2. संयुक्त समूह में ग्रे सूची वाले देशों की प्रगति की समीक्षा की जाती है। भारत एशिया प्रशांत संयुक्त समूह (एपीजेजी), यूरोप/यूरेशिया मध्य पूर्व संयुक्त समूह (ईईएमईजेजी) का सक्रिय सदस्य है। भारत का योगदान भागीदारी से परे है, क्योंकि यह नियमित रूप से एफएटीएफ के आपसी मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए विशेषज्ञ प्रदान करता है। अफ्रीकी संयुक्त समूह की माली में आगामी ऑन-साइट यात्रा में, भारत प्रमुख समीक्षक के रूप में एक विशेषज्ञ भी प्रदान कर रहा है।
भारत एफएटीएएफ ढांचे में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है, जिसके प्रतिनिधिमंडल प्रमुख (एचओडी) एफएटीएएफ संचालन समूह के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, जो उच्च-स्तरीय निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, भारत वैश्विक एएमएल/सीएफटी क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण सुनिश्चित करते हुए प्रशिक्षण परियोजना दल में सह-नेता के रूप में कार्य करता है। भारत जोखिम प्रवृत्तियों और विधियों समूह (आरटीएमजी) में सह-अध्यक्ष का पद भी रखता है, जो दुनिया भर में उभरते धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों की पहचान और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार एक कार्य दल है। भारत राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन परियोजना दल, परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति परियोजना दल, आभासी परिसंपत्ति परियोजना दल, ऑनलाइन बाल यौन शोषण परियोजना दल, साइबर सक्षम धोखाधड़ी परियोजना दल आदि सहित विभिन्न परियोजना दलों के काम में शामिल रहा है।
भारत ने एफएटीएएफ से संबंधित कई बैठकों की मेज़बानी करके एफएटीएएफ के साथ अपने संबंध को और मज़बूत किया है, जिससे वैश्विक एएमएल/सीएफटी समुदाय में इसकी नेतृत्वकारी भूमिका और मज़बूत हुई है। नीचे दी गई तालिका में भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है:

कार्यक्रम का नाम	तारीख	स्थान
पारस्परिक मूल्यांकन के लिए एफएटीएएफ/एपीजी/ईएजी द्वारा एफएटीएएफ अनुशंसाओं की प्रभावशीलता पर देश प्रशिक्षण	14 -16 मार्च, 2023	नई दिल्ली
एफएटीएफ संयुक्त विशेषज्ञ बैठक (जेईएम)	3 - 6 अप्रैल, 2023	नई दिल्ली
एपीजेजी बैठक	7 - 8 सितंबर, 2023	नई दिल्ली
एपीजी वार्षिक टाइपोलॉजीज और क्षमता निर्माण कार्यशाला	28 नवंबर – 1 दिसंबर, 2023	नई दिल्ली
41वीं ईएजी प्लेनरी	25 - 29 नवंबर, 2024	इंदौर, मध्य प्रदेश

3. कुछ आगामी कार्यक्रम हैं जिनकी मेजबानी भारत करेगा जैसे कि एफएटीएफ निजी क्षेत्र सहयोग मंच (पीएससीएफ) की बैठक जो 25 से 27 मार्च, 2025 तक मुंबई में होगी और एफएटीएफ संयुक्त मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण (जेएटी) जो 7 से 11 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में होगा ।

4. औपचारिक संबंधों से परे, भारत के विभागाध्यक्ष पूर्ण बैठकों के दौरान एफएटीएएफ सदस्य क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं, राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक एएमएल/सीएफटी समुदाय के बीच एक मजबूत और सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाते हैं। भारत नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) बैठकों के माध्यम से एफएटीएएफ के साथ लगातार संचार सुनिश्चित करता है, जिससे इसके समन्वय और सहयोग को और मजबूती मिलती है। इसके अलावा, भारत क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करके पड़ोसी देशों को अपनी विशेषज्ञता और समर्थन प्रदान करता है, जिससे एफएटीएएफ के जनादेश को आगे बढ़ाया जाता है और क्षेत्रीय एएमएल/सीएफटी ढांचे को मजबूत किया जाता है।

अनुलग्नक - III

वित्तीय वर्षवार कुल एफडीआई प्रवाह
अप्रैल, 2000 से दिसंबर, 2024 तक

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	कुल एफडीआई अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
1	2000-01	4,029
2	2001-02	6,130
3	2002-03	5,035
4	2003-04	4,322
5	2004-05	6,051
6	2005-06	8,961
7	2006-07	22,826
8	2007-08	34,843
9	2008-09	41,873
10	2009-10	37,745
11	2010-11	34,847
12	2011-12	46,556
13	2012-13	34,298
14	2013-14	36,046
15	2014-15	45,148
16	2015-16	55,559
17	2016-17	60,220
18	2017-18	60,974
19	2018-19	62,001
20	2019–20	74,391
21	2020-21	81,973
22	2021-22	84,835
23	2022-23	71,355
24	2023-24	71,279
25	2024-25 (24 दिसंबर तक)	62,483

अनुलग्नक - IV

एक व्यापक विवेकपूर्ण विनियामक के रूप में, आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए निम्नलिखित प्रमुख विवेकपूर्ण विनियमन निर्धारित किए हैं:

- ऋण जोखिम (सभी एनबीएफसी के लिए), बाजार जोखिम (केवल एसपीडी के लिए) और परिचालन जोखिम (जोर नहीं दिया गया) के लिए पूंजी पर्याप्तता, एनबीएफसी की वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित नियामक पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंड खाते में तनाव के लिए प्रावधान करते हैं। एनबीएफसी द्वारा लागू भारतीय लेखा मानकों के मामले में, ये मानदंड विवेकपूर्ण आधार के रूप में कार्य करते हैं।
- ऋण/निवेश के संकेन्द्रण से उत्पन्न जोखिमों को दूर करने के लिए एक्सपोजर मानदंड (एनबीएफसी-यूएल के लिए बड़े एक्सपोजर ढांचे सहित),
- विनियामक प्रतिबंध जैसे मूल्य निर्धारण के लिए ऋण आदि, सुरक्षित ऋणों के लिए पर्याप्त ऋणाधार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए,
- बाजार में अत्यधिक मंदी के परिदृश्य में एएलएम जोखिमों और एलसीआर संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनबीएफसी के पास ग्राहकों, ऋणदाताओं और अन्य हितधारकों के प्रति अपने प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित चलनिधि हों।

व्यावसायिक आचरण संबंधी पहलुओं के संबंध में, आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए निम्नलिखित प्रमुख आचरण विनियम निर्धारित किए हैं:

- पीएमएलए और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने ग्राहक को जानें/धन शोधन निरोधक/वित्तीय या आतंकवाद निरोधक प्रावधान,
- कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंड अर्थात नियंत्रण/प्रबंधन में परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन, बोर्ड समितियां, मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, निदेशकों/निदेशकों के रिश्तेदारों के लिए जोखिम पर प्रतिबंध, मुआवजा ढांचा, विस्तृत प्रकटीकरण मानदंड आदि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनबीएफसी हितधारकों/ग्राहकों के हित में कार्य करें और एनबीएफसी का प्रबंधन सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक न हो।
- एनबीएफसी क्षेत्र के सतत विकास के लिए एनबीएफसी के परिचालन में निष्पक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता,
- शिकायत निवारण तंत्र, लोकपाल योजना, ग्राहक जागरूकता अभियान आदि, एनबीएफसी के परिचालन में निष्पक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने तथा वित्तीय पहलुओं पर ग्राहकों को शिक्षित करने जैसी ग्राहक संरक्षण पहल।

******